बेटियां योग्यता, समझ, धैर्य, साहस, परिश्रम, संघर्ष करने में कमतर नहीं हैं, लेकिन फिर भी...

राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष

बराबरी का दर्जा अभी भी सपना है..!

विशेष...!
गोविन्द बड़ोने

बेटियां योग्यता, समझ, ज्ञान, विवेक, धैर्य, साहस, परिश्रम,संघर्ष करने में कमतर नहीं है. उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल से समाज को दांतों तले ऊंगली दबाने को मजबूर किया है. बहुतायत बेटियों में कौशल दिखाने का जज्बा है अगर समाज और सिस्टम उन्हें अनुकूल माहौल प्रदान करने में सफल हो. बेटियों को हर क्षेत्र में अवसर मिले तो वे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का हौंसला रखती है. बेटियां हर क्षेत्र में उड़ान भरने का माद्दा रखती है. हम उन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ते हुए देखना चाहते है यह विचार हमें करना है. हम बेटियों को जितनी अधिक ऊंचाईयों पर पहुंचाने का संकल्प लेते है, वे उतनी ही अधिक ऊंचाई पर पहुंचकर हमारा मान बढ़ाने को तैयार बैठी है.

भारत सरकार ने 2008 से प्रति वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना शुरू किया था. यह दिवस मनाते हुए आज 18 वर्ष पूर्ण हो रहे है. यूं कहे कि बालिका दिवस मनाते हुए समाज आज बालिग हो गया है. लेकिन इसके उद्देश्य की पूर्ति के आंकलन से यहीं लगता है कि समाज बालिका के विषय में बेहतर सोचने में नाबालिग ही है. राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य थे उनमे - बालिकाओं के अधिकारों और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समाज में लैंगिक भेदभाव को कम करना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को बढ़ावा देना. हम गर्व के साथ यह कहने की स्थिति में नहीं है कि हमने उद्देश्य की पूर्ति का 25 प्रतिशत लक्ष्य भी पूरा किया है. हमने प्रचार-प्रसार का शोर खूब किया, किंतु व्यवहारिक तौर पर इसका असर किसी से छुपा नहीं है. शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है तो शिक्षा के संसाधन बढ़ाने में कंजूसी की है. लैंगिक भेदभाव को कम करने का दावा किया है लेकिन हम पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता से बाहर नहीं आये है. आज भी बालिका के बाद जन्म लेने वाला बालक दिलखुश करने का आधार बनता है. बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर शासन-प्रशासन कितना सजग है यह अस्पतालों, पुलिस थानों के आंकड़ों को देखने से पता चलता है. शिशु मृत्यु दर, कुपोषण से पीड़ित बालिकाओं का प्रतिशत बालकों से अधिक मिलता है.बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं यह शब्द भी नारा प्रतीत होता है. बालिकाओं की दिशा बदलने के प्रयासों और प्रगति में काफी अंतर है. बेटियों के प्रति संवेदनशीलता बरतने का दावा करने वाले समाज,सरकार और सिस्टम में एकरूपता नहीं है. इन हालातों से लगता है बेटियों के लिये बराबरी का दर्जा अभी भी सपना ही है. इसके अनेकों उदाहरण में दिखाई देते है. हाल ही में हरियाणा के जींद जिले के ऊचाना क्षेत्र में नो बालिका के बाद 10 वीं संतान के रूप में हुए बालक का नाम दिलखुश रखा गया। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसका मतलब यह हुआ कि नौ बालिकाओं से परिवार ने खुशी का अनुभव नहीं किया था. ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे पास पड़ोस में देखे सुने जा सकते है. यही स्थिति बालिकाओं की शिक्षा को लेकर है. उन्हें पढ़ाने के प्रति जागरूकता, पर्याप्त संसाधनों का अभाव है. राजगढ़ जिले के ब्यावरा स्थित सबसे बड़े कन्या उमावि में करीब 2500 बालिका अध्ययनरत है. स्थानाभाव के कारण यहां के अध्यापक रोज यह प्रार्थना करते है कि सभी बालिकाएं एक साथ पढने न आ जाए. जो थोड़ी बहुत आती है उनके लिये खेल मैदान तो छोड़ इतनी जगह भी नहीं है कि वे एक साथ लंच कर सके. इसलिये विद्यालय उन्हें ग्रुपों में लंच के लिये छोड़ता है. इसी प्रकार वाशरूम जाने के लिये भी बालिकाओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है. इस विद्यालय को पीएमश्री का तमगा भी दे दिया है लेकिन सुविधाएं सामान्य विद्यालय से भी गई गुजरी है.

शिक्षा, सुरक्षा के इंतेजाम नहीं होने का दुष्परिणाम है कि जिले में बालिकाओं को परिवार, समाज कम उम्र में विवाह बंधन में धकेलने को मजबूर हो जाता है. शिक्षा से चेतना जागृत होने वाले समाज ने बालविवाह के नुकसान को समझा और शिक्षा के लाभ को महसूस किया है. दलित, पिछड़े वर्ग से जुड़े बड़े वर्ग ने शिक्षा और सुरक्षा के अभाव में हताश हो बालिकाओं को पढने से वंचित रख बालविवाह करना नीयति मान ली है. दूसरी ओर जहां भी समाज, सरकार और सिस्टम ने बालिकाओं की हौंसलाफजाई की है वहां के परिणाम संतोषप्रद आए है. कई बालिकाओं ने स्व प्रेरित व स्व जागरूक हो आगे ब?ी है. उन्होंने कम संसाधनों में खुद के पुरूषार्थ से सफलता का मुकाम हांसिल किया है. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े विभिन्न समाजो में जागरूकता तो आ रही है लेकिन बालिका शिक्षा के लिये अनुकूल वातावरण नहीं होने से उन्हें उत्साही माहौल नहीं मिल पा रहा है. जो जाति - समाज सक्रिय होकर आगे बड़ रहे है उनकी बेटियां निरक्षरता के कलंक व बालविवाह के दंश से मुक्त होने की दिशा में आगे बड़ रही है. बेटियां योग्यता, समझ, ज्ञान, विवेक, धैर्य, साहस, परिश्रम,संघर्ष करने में कमतर नहीं है. उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कौशल से समाज को दांतों तले ऊंगली दबाने को मजबूर किया है. बहुतायत बेटियों में कौशल दिखाने का जज्बा है, अगर बेटियों को हर क्षेत्र में अवसर मिले तो वे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का हौंसला रखती है. बेटियों को गांवों से शहर में आकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने, खेल के मैदान में हुनर दिखाने, नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने , अपने कौशल से रोजगारों का सृजन करने की हिम्मत देने की आवश्यकता है. हमें बेटियों को बड़े फलक पर सोचने के लिये प्रेरित करना होगा।

उनकी अपेक्षा के अनुरूप माहौल मिल जाए तो बेटियां हर क्षेत्र में उड़ान भरने का माद्दा रखती है. हम उन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ते हुए देखना चाहते है यह हमें तय करना है. हम बेटियों को जितनी अधिक ऊंचाईयों पर पहुंचाने का संकल्प लेते है, वे उतनी ही ऊंचाई पर पहुंचकर हमारा मान बढ़ाने को तैयार बैठी है.

बाल विवाह

पिछले 3 महीनों में 52 बाल विवाह के प्रकरण आए सामने

झगड़ा और नातरा प्रथा के प्रकरण

वर्ष-2023
प्रकरण-143

वर्ष-2024
प्रकरण-191

वर्ष-2025
प्रकरण-197

हमने विभिन्न अभियानों के के माध्यम से बाल विवाह के प्रकरणों को मौके पर जाकर रूकवाया है. जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से हमने झगड़ा और नातरा जैसे मामलों में कार्यवाही की है. सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे है. इस बुराई को मिटाने हम सभी प्रतिबद्ध है.

श्यामबाबू खरे,
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजगढ़

बेटी का दर्द !
मुझे जीते जी मत मारो...

कुप्रथाएं

बाल विवाह एक ऐसा अभिषाप है जिसका दंश झेलने वाली कई बेटियों की जिंदगी राख हो चुकी है. वे जीते जी स्वयं को मृत प्राय मान चुकी है. कुरूति को परंपरा मानकर बेटियों के जीवन में जहर घोलने वाले समाज के कुछ अनपढ़ लोगो ने बेटियों का बाल विवाह कर उन्हें जैसे बचपन में ही मार दिया है. राजगढ़ जिले में औसतन डेढ़ से दो हजार बालविवाह प्रति वर्ष होते है. इनमें 500 से अधिक विवाह तो 10 से 15 वर्ष की आयु के होते है. पांच-दस वर्ष पूर्व बाल विवाह का यह आंकड़ा तीन से चार हजार तक रहता था. प्रशासन के सक्रिय रहने से इसमें गिरावट तो आई है लेकिन दकियानुसी परंपरा पर विराम नहीं लगा है. प्रशासन ने गत वर्ष 2025 में करीब 52 बालविवाह पर रोक लगाने का आंकड़ा बताया है लेकिन खिलचीपुर क्षेत्र की होड़ा माताजी के यहां बड़ी तादात में विवाह की पाती लिखाई जाती है इसकी पुष्टि गांव के लोग करते है. यद्यपि महिला बाल विकास, पुलिस, प्रशासन ने बाल विवाह पर रोक लगाने गांवों में तैनात प्रत्येक कर्मचारी को पाबंद किया है. इससे संख्या में तो गिरावट आई है लेकिन यह संतोषजनक नहीं है. बालविवाह की विभीषिका यह है कि बेटी को गर्भ में नहीं जन्म देने के बाद उसके जीवन को नर्क बनाकर उसे जीवन भर यातना देने का इंतजाम कर दिया जाता है। दशकों से यह दुस्साहस उनके अपने करते है. यहां विवाह संस्कार नहीं व्यापार बना हुआ है. बालविवाह की कुप्रथा से शुरू होने वाले व्यापार का लाभ समाज के तथाकथित ठेकेदार उठाते है. बालविवाह टूटने पर राजगढ़ जिले में दशकों से एक कुप्रथा प्रचलित है. इसमें बालिका का दूसरा विवाह करने पर बेटी के पिता अथवा जिस नये परिवार में शादी हो रही है वह पहले वाले दूल्हे के पिता को लाखों रूपये देता है. इसे गांव की भाषा में झगड़ा तोडना कहा जाता है. इस झगड़े के बहाने एक, दो नहीं अनेको जगह लोग बेटियों की खरीद फरोक्त कर देते है. बेटियों की पुकार है कि पुलिस-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार सिंचाई के इंतेजाम कर मजदूर के पलायन पर रोक लगाई उसी प्रकार वे बाल विवाह पर भी रोक लगाकर उनके जीवन को स्वर्ग बनाने की दिशा में ठोस पहल कब करेंगे.

बाल विवाह के कई दुष्परिणाम भोग रही हैं बेटियां

बाल विवाह के कारण नाबालिग बेटियां मां बन रही है. बेटियों और जन्म लेने वाले शिशु दोनो का जीवन खतरे में होता है. राजगढ़ जिले में पिछले वर्ष करीब 100 से अधिक नाबालिग मां बनी है.इसके कई सामाजिक दुष्परिणाम सामने आते है.कुरूतियों के विरूद्ध अलख जगाने क काम में लगे अहिंसा वेलफेयर सोसायटी के मनीष दांगी बताते है कि हमने समाज की पढ़ी लिखी बेटियों से ही कुरूतियों पर प्रहार कराना शुरू किया है. हम उन्हीं के माध्यम से गांवों में चौपाल चर्चा कर उन्हें समझाते है. नई पीढ़ि के लोग समझने लगे है.

एक तथ्य यह भी सामने आया है कि बालविवाह, नातरा प्रथा आदि कुरूतियों से घिरा समाज अगर अन्य जाति-समुदाय, वर्ग के बीच रहता है तो उनमें वहां सुधार नजर आता है. छापीहेड़ा,लसूडली, नांदनी, चांदनी, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर के कुछ गांव ऐसे है जहां विभिन्न जाति समुदाय के लोग निवास करते है. इन्हीं गांवों में अगर बालविवाह नहीं करने वाला समाज रहता है तो फिर बाकी लोग भी इनका अनुसरण करने लगे है. मतलब संगति का असर आ रहा है. अगर गांवों में शिक्षा का प्रभाव बड़े और कालीपीठ, धनवासकलां, भोजपुर जैसे बड़े क्षेत्रों में अगर शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार हो तो गांवों की बालिकाएं शहर आने के भय से पढ़ाई छोड़ने को विवश नहीं होगी.

-उत्तम शर्मा, राजगढ़

बेटियों को सभी स्कूलों में मिले महिला शिक्षक

जिले के लगभग सभी एकीकृत स्कूलों में बालिकों की अच्छी संख्या दर्ज है. वहीं प्रायमरी स्कूलों में स्थानीय स्तर पर बालिकाएं पढ़ने जाती है. लेकिन बालिकाओं को सुरक्षा और पढ़ाई में मनौवैज्ञानिक रूप से कम्फर्ट के लिए अधिकांश स्कूलों में महिला शिक्षकों की तैनाती नहीं है. तथ्य पढ़ाना संकुल में सामने आया. जनशिक्षा केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार एकीकृत स्कूलों की संख्या 9 है जबकि 5 में महिला शिक्षक ही नहीं है. साथ ही प्रायमरी स्कूलों की संख्या 10 है और उनमें भी 9 में महिला शिक्षिकाएं नहीं है. यह सिर्फ आंकड़े एक संकुल के है. यदि जिले भर में नजर दौड़ाई जाए तो पदस्थापना और मनचाहे स्कूलों की बंदरबांट में महिला शिक्षकों की तैनाती शतप्रतिशत स्कूलों में नहीं है. बालिकाओं को अपनी समस्याएं, पढ़ाई में दिक्कतें यदि खुलकर बतानी हो तो महिला शिक्षकों से अच्छा साथी नहीं है. लेकिन स्कूलों में बालिकों के लिए उनकी कई जगह तैनाती ही नहीं है. जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस ओर भी देखना चाहिए.

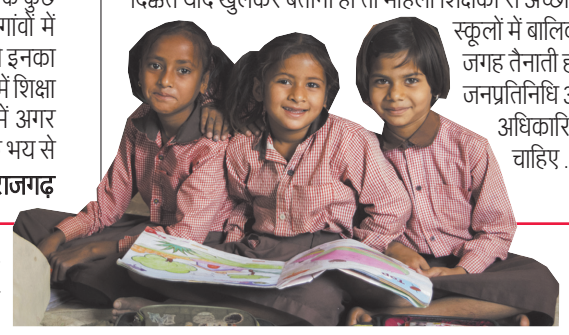

वीरेन्द्र सिरोलिया, पड़ाना

बढ़ानी होगी शिक्षा सुविधाएं

जिले के सीमांत ईलाकों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शासन और प्रशासन को शिक्षा विभाग के साथ विशेष प्रयास करने होंगे. यहां नवभारत ने सीमांत कस्बे माचलपुर से जमीनी स्थिति तलाशने का प्रयास किया है. कस्बे में एकमात्र हाई स्कूल भवन है और वह भी काफी पुराना और अब जर्जर हालत में है. रंगाई पुताई के कारण वह ठीक ठाक नजर आता है. स्कूल में कुल 312 छात्र है और ये सभी 10 छोटे-छोटे कक्षों में बैठकर पढ़ाई करते है. वहीं इन्हें पढ़ाने के लिए 14 शिक्षकों की तैनाती है. स्कूल में खेल मैदान नहीं है इसलिए बड़े स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होते है. एक प्यून पूरे स्कूल को संभालता है. आसपास के ईलाकों जैसे लसूडलिया, डूंगरी, मौली, मल्हालपुरा, मल्हारगढ़, नांदरी, डोब, बामनियाखेड़ी आदि से बालिकाएं इसी स्कूल में पढ़ने आती है. ऐसे में नया और विशाल भवन, आसपास गांवों में स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए. ये सीमांत गांव है, प्रतिभा सम्पन्न है लेकिन सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं है. **ओमप्रकाश जायसवाल, माचलपुर**

बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि

हमने 50 हजार पालकों को प्री स्कूल एजुकेशन से जोड़ा. आंगनबाड़ी के माध्यम से हम प्रयास कर रहे है प्री एजुकेशल बच्चियों को मिले. एलीमेंट्री एज्युकेशन दे रहे है. एनजीओ के माध्यम से प्री नर्सरी ट्रेनिंग करवा रहे है. बोर्ड में ड्रॉप आउट का रिजल्ट पिछले बार से अच्छा रहा है. इसमें सुधार आया है. बालिकाओं में उत्तीर्ण का प्रतिशत बढ़ा है. समाज में जागरूकता आई है. इसके आलावा जो भी केसे बेटियों से जुड़े आते है जिन्हें हायर एजुकेशन में जाना है, मैने दो बेटियों को पिछले दिनों शहरों में पढ़ने के लिए कोचिंग से बात कर भेजा. जो भी बेटियां आगे उच्च शिक्षा में मेहनत कर आगे जाना चाहतीं है हम उन्हे पूरा सहयोग दे रहे है. हम अपनी ओर से नवाचार कर रहे है. हमने कुछ मामलों में बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए भोपाल, इंदौर के कोचिंग संस्थानों से सम्पर्क कर बेटियों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने के प्रयास किए है. सुरक्षा को लेकर हम जिला प्रशासन, पुलिस और नगरीय निकायों को सौ प्रतिशत सीसीटीवी कवरेज कर रहे है. नरसिंहगढ़ की घटना के बाद हम संवदेशनशील तरीके से प्रयास कर रहे है. हम संवदेनशील स्थानों पर विशेष नजर बनाए हुए है. बाल विवाह को रोकने के लिए भी हम शासकीय योजनाओं के माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे है. हम परिजनों, गांव-गांव सम्पर्क बना रहे है. जनसुनवाई में झगडा नातरा के प्रकरणों में हम एफआईआर करवा रहे है.

डॉ गिरीश कुमार मिश्रा
जिला कलेक्टर, राजगढ़

पचोर: खेल मैदान और प्रयोगशाला भवन की कमी

संसाधन...!

पचोर कन्या उमावि और पीएमश्री में वर्तमान में 20 से 22 कक्ष है जिसमें चार-पांच कक्षा में लैब संचालित है. प्रयोगशाला के लिए पर्याप्त संसाधन संसाधन एवं फर्नीचर भी है लेकिन भवन की कमी के कारण संसाधन धूल खा रहे हैं छात्राओं को प्रयोगशाला का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वही छात्राओं संख्या के मान से कक्षा की काफी कमी है. प्राचार्य श्रीमती मंजू गुप्ता ने बताया कि सुचारू रूप से विद्या अध्ययन के लिए कम से कम 10 कक्ष की आवश्यकता है. वही प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशाला भवन की आवश्यकता है. राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल द्वारा विद्यालय में कमरों की कमी को पूरी करने के लिए आठ कक्ष निर्माण के लिए एक करोड़ 56 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है लेकिन अभी निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है. छात्राओं की संख्या के हिसाब से 2 शौचालय एवं चार-पांच यूरिनल और होना चाहिए. एक तकनीकी समस्या बालिकाओं के सामने उत्पन्न हो रही है जिससे साइकिल उपलब्ध नहीं हो पा रही है. वजह यह है कि वार्ड नंबर एक बिलापुरा, वार्ड क्रमांक 9 कंजरपुरा वार्ड क्रमांक 4 गंगाहोनी की दूरी कन्या शाला से 3 से 4 किलोमीटर पड़ती है. लेकिन यह नगर परिषद के वार्ड की सीमा में आते हैं. पीएम श्री शा कन्या उ मा वि पचोर में कुल 1280 छात्राए अध्यनरत है. जिसमे से 818 छात्राएं 9वी से 12वी तक, 332 छात्राए 6से 8 और 130 छात्राए 1 से 5 में अध्ययन रत हैं. इस शिक्षा सत्र से नर्सरी एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं शुरू हो चुकी है जिसमे 16 छात्राए है. खेल का मैदान की विद्यालय में कमी है जिससे छात्राओं को खेल गतिविधियों भाग लेने में परेशानी होती है.

पुरषोतम वैष्णव, पचोर

सरकार, समाज और सिस्टम अगर सक्रिय हो जाएं तो...

उड़ान भरने को तैयार हैं बेटियां...!

गौरव चौरसिया

राजगढ़ 23 जनवरी, का. सरकार, सिस्टम के सहयोग, समर्थन और भरोसे से कुरूतियों, पिछड़ेपन, अशिक्षा से जूझने वाला समाज जागृत अवस्था में नजर आने लगता है. परिवर्तन की प्रक्रिया सामुहिक प्रयासों का परिणाम होती है. समाज परिवर्तन के लिये साहस जुटाने वाले व्यक्ति को अगर सिस्टम समर्थन का भरोसा दे तो हालात शीघ्र बदले जा सकते है.

राजगढ़ जिले के संदर्भ में देखा जाए तो यहां की बड़ी ग्रामीण आबादी कुरूतियों, पिछड़ेपन, अशिक्षा से जूझ रही है. इस आबादी वाले क्षेत्र में बाल विवाह, नातरा, झगड़ा प्रथा जैसी कुरूतियां कलंक के रूप में पैर पसारे हुए है.

इन कुरूतियों से जिले की बड़ी आबादी दशकों से अनेकों समस्याओं से पीड़ित है. इनका असर उनके जीवन स्तर पर पड़ रहा है. इन कुरूतियों ने ग्रामीणों को लड़ाई-झगड़ा, पुलिस, कोर्ट-कचहरी के चक्कर, चोरी, मारपीट, आगजनी जैसी घटनाओं से प्रताड़ित कर रखा है. ग्रामीणों को गरीबी से भी जूझने को मजबूर कर रखा है.

इस समस्या को दूर करने के प्रयास मैदानी स्तर पर कम सरकारी कार्यालय स्तर पर अथवा मीडिया स्तर पर अधिक हुए है. परिणाममूलक कार्य करने की मानसिकता से मैदानी स्तर पर समाज को जोड़ते हुए अभियान चलाया जाए तो स्थिति बदलना शुरू हो सकती है.

यह संतोष का विषय है कि शासन-प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, जाति समाज के वरिष्ठजनो के प्रयासों से बालविवाह में कमी व शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी हुई है.

यह सर्वविदित है कि बालविवाह और नातरा प्रथा की कुरूती राजगढ़, खिलचीपुर क्षेत्र में सर्वाधिक है. इन दोनो क्षेत्रों में बड़ी आबादी दांगी, सौंधिया, तंवर समाज की है. दांगी, सौंधिया समाज में जागरूकता का प्रतिशत बड़ा है. तंवर समाज भी जागरूक होने लगा है. राजगढ़ के तंवरवाड़ क्षेत्र में बालिकाओं को पढने के लिये प्रेरित किया जा रहा है.

धनवासकलां निवासी शिक्षक सर्जन सिंह तंवर इसके उदाहरण है. उन्होंने अपनी भतीजे किरण तंवर का बाल विवाह नहीं होने दिया. आज किरण राजगढ़ कालेज की स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा है. इसी प्रकार टांडी की चिंता तंवर, हिरनखेड़ा की सीमा तंवर, युवक जितेन्द्र तंवर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है. इनका कहना है कि हम पढ़ाई करने लगे तो हमें समझ आया कि बालविवाह से जीवन कैसे नर्क में पहुंच जाता है.

अगर सरकार, समाज और सिस्टम सक्रिय होकर लोगो को जागृत करने की दिशा में रणनीति के साथ जुटे तो बेटियां उड़ान भरने को तैयार है. बेटियों की उड़ान समूचे समाज की तरक्की का रास्ता खोल सकती है. आवश्यकता हमें बेटियों को उड़ान भरने के लिये बेहतर वातावरण निर्मित करने की है.